

मोबाइल उस एक्सरे मशीन में डाला, उसके बाद उसके सिम कार्ड में जो फोन बुक थी, वह पूरी की पूरी गायब हो जाती है। मैंने पूछा कि क्यों गायब हो गई, तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन में जो एक्सरे करते हैं, उसमें जो rays होती हैं, उससे यह गायब हो जाती है। तो माननीय मंत्री जी, सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन आजकल मोबाइल असुरक्षित हो गया है, इसकी सुरक्षा कैसे होगी ... (व्यवधान)...

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति जी, मुझे तो मालूम नहीं कि आपके लिए कौन सी कंपनी मोबाइल बनाती है ... (व्यवधान)... बाकी बातें जो आपने कहीं, मैं आपकी एकाध बात स्वीकार कर सकता हूँ कि किसी का मोबाइल इधर का उधर हो गया हो, लेकिन यह मैमोरी की जो बात है, हम भी जाते हैं, हम भी सिक्योरिटी चैक के through जाते हैं, हमारे मोबाइल का आज तक नंबर नहीं गया है। ... (व्यवधान)... सभापति जी, यह प्रश्न एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के बारे में था और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए कृपा करके हम भी आपसे थोड़ी सुरक्षा चाहते हैं।

Maintenance of cemeteries

*187. SHRI MAHENDRA MOHAN: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the foreign citizens are visiting India to see the cemeteries of their forefathers in Lucknow, Kanpur, Meerut and other places;

(b) whether it is also a fact that their number is likely to increase in the year 2007 in view of 150th year of the First War of Independence in 1857; and

(c) if so, the arrangements made by Government in this regard for the tourists and the maintenance of these places?

THE MINISTER OF TOURISM AND CULTURE (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The protected cemeteries with the Archaeological Survey of India are maintained and conserved in accordance with the Archaeological norms and principles. All the field staff of Archaeological Survey of India has been directed to keep these monuments in presentable condition and extend

full cooperation to the visitors. Ministry of Tourism, under its scheme of Product/Infrastructure Development for Destinations and Circuits extends central financial assistance to States/UTs for development of tourism infrastructure of places prioritized in consultation with them. In addition, the State/UT Government concerned have also made suitable arrangements for the tourists visiting various places.

श्री महेन्द्र मोहन: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता का युद्ध जो 1857 में हुआ था जिसकी 150वीं जयंती आने वाली है, इस मौके पर यूके वगैरह से बहुत से टूरिस्ट हमारे यहां आ सकते हैं, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन टूरिस्टों को यहां लाएं, जिससे हमारा टूरिज्म बढ़े? इसके साथ ही साथ इन्होंने अपने उत्तर में पार्ट "सी" में यह बतलाया है कि हम कुछ फंड देते हैं और ये बहुत से स्थान पर जहां पर cemeteries हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उन cemeteries के लिए और जो आगंतुक आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनके लिए कितना धन इन्होंने allocate किया है, जिससे वहां की cemeteries की अच्छी व्यवस्था की जा सके और जो टूरिस्ट आए, वे उन cemeteries पर जाकर इस कार्य का सही रूप से कर सकें, इसके लिए कितना धन आपने आवंटित किया है, यह मेरा पहला सप्लीमेंटरी है।

श्रीमती अंबिका सोनी: सभापति जी, यह सही बात है कि हम अपनी आजादी के संघर्ष के डेढ़ सौ साल मना रहे हैं और इस दौरान हमें उम्मीद है कि विदेश में बहुत भारी तादाद में पर्यटक भारत आएंगे और उनके यहां आगमन के लिए केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें, कई योजनाएं, कई सर्किट, टूरिज्म के नए प्रॉडक्ट्स तैयार कर रही हैं जिससे कि हर वर्ग के पर्यटक को उनकी दिलचस्पी का टूरिज्म हम यहां उपलब्ध करवा सकें, लेकिन जहां तक cemeteries की बात की गई है, यह सच बात है कि अक्सर लोग यहां अपने पूर्वजों की कब्रों पर, cemeteries पर आते हैं और हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ये सहूलियतें देने के प्रयास किए हैं कि वहां कम से कम civic amenities वगैरह उपलब्ध कराई जाएं और पूरी cemeteries की जो देखभाल है, उसके लिए कुछ standards maintain किए जाएं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, पिछले 3 सालों में लखनऊ की कई cemeteries हैं, मैं उनके नाम पढ़ देती हूँ और बता देती हूँ कि कितना खर्च कहा-कहां कब-कब हुआ है। यह Machi Bhawan Cemetery है हरदोई में, झांसी में Memorial cemetery है, कानपुर में कचहरी सिमिट्री है। कानपुर की कचहरी सिमिट्री पर 4 लाख, 71 हजार रुपए का खर्च हुआ है। झांसी की Memorial cemetery पर 1,04,400 रुपए का खर्च किया गया।

श्री महेन्द्र मोहन: माननीय मंत्री महोदया, जब हम cemeteries पर जाते हैं, तो देखते हैं कि cemeteries की हालत बहुत खराब है, तो जो हमारे विदेशी पर्यटक आएंगे, उन पर क्या असर

पड़ेगा? जिससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता था, ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, इस ओर आप ध्यान दें। विशेष रूप से ये cemeteries अधिकतर उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर में cemeteries हैं। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि दिल्ली से कोई यातायात की भी व्यवस्था, कोई एयरलाइन कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि मंत्री महोदया इस पर ध्यान दें और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था कराई जाए, तभी यह कार्य होगा, अन्यथा हमारी बहुत बदनामी होगी और हमारे देश में टूरिज्म का बहुत बड़ा loss होगा।

श्रीमती अम्बिका सोनी: सर, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक फर्मा रहे हैं कि जब तक हम और सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक आने वाले पर्यटकों के ऊपर एक अच्छा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहां बताना चाहती हूँ कि जहां तक पर्यटन का सवाल है, सुविधाएं उपलब्ध करवाने का सवाल है और उनके विकास का सवाल है, तो यह प्राथमिकता प्रदेश की सरकारों को देनी है। हम लोग पर्यटन के विकास के लिए हर प्रदेश सरकार को जो भी 15-20 करोड़ रुपया देते हैं, priorities स्टेट गवर्नमेंट्स फिक्स करती हैं। आप भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से कहें और मैं भी इस सदन की चिन्ता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को दोबारा जरूर लिखूंगी कि उन्हें cemeteries पर ज्यादा खर्च करना चाहिए, ताकि पर्यटकों को और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

श्री मोतिउर रहमान: सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश की आजादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और ऐसे लोगों की कब्रें बिहार और हिन्दुस्तान के जिस कोने में भी हैं, सरकार उनकी कब्रों को घेर कर उन पर उनके इतिहास को लिखना चाहती है या नहीं?

श्रीमती अम्बिका सोनी: सर, कुछ राष्ट्रीय स्मारक हैं, जहां केन्द्रीय मंत्रालय पूरा योगदान देता है। हम जितने साधन उपलब्ध करवा सकते हैं, हम प्रदेश सरकारों को जरूर भेजते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्मारकों की जिम्मेदारी एक तरह से केन्द्रीय सरकार की बनती है। इसके अलावा बहुत से और स्मारक और समाधियां हैं, जिनकी स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत देखभाल की जाती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस साल, जब हम अपनी आजादी की पहली लड़ाई का 150वां साल मनाने जा रहे हैं, हम पूरे देश भर में यह प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से जहां स्मारक बन चुके हैं और कई जगहों पर जहां और स्मारक बनने चाहिए, उनकी सूची तैयार हो रही है, ताकि इस साल के दरम्यान, जब हम 150 years of the first freedom struggle मनाने जा रहे हैं, हम यह कोशिश करना चाहते हैं कि ये बनाई जाएं और अच्छे पैमाने पर बनाई जाएं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, यह सवाल तो cemeteries के रखरखाव के बारे में है, लेकिन चूंकि 1857 का जिक्र हो रहा है, इसलिए मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूँ कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध में कुछ लोग तो जाने-पहचाने शहीद हैं, लेकिन

अगणित अज्ञात शहीद ऐसे हैं, जिनके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। चूंकि हम यह 150वां साल मनाने जा रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों की कोई सूची प्रकाशित करके उनकी प्रतिमाएं उनके गांवों में, नगर-चौराहों में लगाने की कोई इस तरह की योजना सरकार ने बनाई है, जिसे कम-से-कम 150वें साल में हमारे बच्चों को यह पता चल जाए कि 1857 में कौन से लोग स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए थे?

श्रीमती अम्बिका सोनी: माननीय सभापति जी, सुषमा जी ने जो सवाल किया है, मैं उनको बताना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें हर राजनीतिक दल के नेता सदस्य के रूप में मौजूद हैं और दूसरे सिविल सोसायटीज से भी सदस्य हैं। वहां यह सुझाव आया था, इस पर गौर किया गया और इसे आगे ले जाने के लिए तय किया गया है। अलग-अलग लोगों को स्टेटवाइज़ सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं, तमाम उन लोगों की याद में, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, कुर्बानियां दीं और हमें आजाद करवाया।

DRI notices on purchase of imported cars

***188. SHRI MOTIUR RAHMAN:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Directorate of Revenue Intelligence has issued notices to a chosen few with regard purchase of imported cars;

(b) if so, the details of the persons to whom DRI had issued notices giving reasons therefor;

(c) whether senior bureaucrats etc. have been let off in the matter of purchase of imported cars; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) The Directorate of Revenue Intelligence has booked cases regarding the import of cars under the EPCG Scheme and TR Rules at concessional rates of duty and the unauthorized transfer of such cars to some individuals. During 2005-06 and 2006-07 (upto July), DRI had seized 113 (of which 103